शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 24-09-2020, वर्ग - BA-II

(4) राज्य-वार सहायता (State-wise Assistance)
अब तक IDBI द्वारा प्रदान की गयी सहायता में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को सबसे अधिक भाग प्राप्त हुआ है। अब IDBI पिछड़े राज्यों के अधिक सहायता देने का प्रयास करता है।

(5) क्षेत्रवार सहायता (Sector-wise Assistance):-
IDBI द्वारा अब ~~तक~~ तक प्रदान की गयी सहायता में निजी क्षेत्र (private sector) का भाग 75.5 % रहा है। अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) का भाग 14.9 %, संयुक्त क्षेत्र का भाग 6.8 %; तथा सहकारी क्षेत्र (cooperative sector) का भाग 2.8 % रहा है।

(6) पुनर्वित सहायता (Refinance Assistance) ⇒
अब IDBI भारत की पुनर्वित

प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। एक अन्य संस्था NABARD भी पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। अप्रैल 1990 से SIDBI भी अब पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने लगा है।

(7) निर्यात ऋणों एवं स्थगित भुगतानों के लिए गारंटियां (Guarantee for Export Loans and Deferred payments) —

विकास बैंक द्वारा ऐसी गारंटीयों की बकाया राशि 360 करोड़ थी। अब यह कार्य निर्यात-आयात बैंक (Exim Bank) द्वारा किया जा रहा है जिसे जनवरी 1982 में स्थापित किया गया।

(8) अन्य विविध कार्य (Other miscellaneous function) —

अन्य भारतीय वित्तीय

निगमों (IFCI, ICICI, LIC, GIC, UTI) संयुक्त बैठकें समय-समय पर विकास बैंक द्वारा आयोजित की जाती हैं जिनमें राज्य-स्तरीय वित्त निगमों (SFC, SIDC) के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। उनमें अंतर-संस्थागत (inter-institutional) मामलों पर विचार विमर्श होता है।

सहायता प्राप्त कम्पनियों की प्रगति की देख रेख के लिए (for monitoring the progress) ऐसी कम्पनियों के संचालक मंडलों में कुछ संचालकों को नियुक्त करने का अधिकार IDBI को है। इस समय 940 कम्पनियों के संचालक मंडलों में IDBI के नामांकित संचालक (Nominee Directors) कार्यरत हैं।

विकास बैंक के अन्य कार्यों

के अन्य कार्यों में अनेक कार्य शामिल हैं। जैसे राज्यों के वित्तीय निगमों एवं तकनीकी संगठनों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन, समय-समय पर इनका निरीक्षण एवं प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, वित्तीय परामर्श अध्ययन अनुसंधान सर्वेक्षण आदि के कार्य तथा विकास एवं प्रबंध संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर विचारगोष्ठियों (seminars) का आयोजन आदि।

(9) नरम उधार योजना (Soft loan Scheme)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1976 में नरम उधार योजना चालू की ताकि कुछ चुने हुए उद्योगों को (अर्थात सिमेंट, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन और चीनी तथा कुछ इंजीनियरिंग उद्योग) को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया ~~गया~~ जा सके जिससे वे अपने प्लांट एवं

मशीनरी के आधुनिकरण, पुनर्स्थापना और नवीनीकरण की योजनाओं को लागू कर सके।

इस प्रकार कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस योजना के अधीन 7.5% ब्याज दर ली जाती है और ~~औ~~ ऋण की अवधि 15 वर्ष रखी जाती है। यह योजना परिवर्तनीयता अनुच्छेद (Convertibity Clause) के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए आकर्षक नहीं थी इसे हटा देने के पश्चात वितरण की गति तेज कर दी गयी।

जनवरी 1984 से नरम उधार योजना का संशोधन कर इसे आधुनिकीकरण के लिए नरम उधार योजना ~~कहा~~ कहा गया ताकि इसके ~~अधीन~~ अधीन योग्य इकाइयों की सहायता की जा सके।